भारतीय शिल्प का अर्थशास्त्र

हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र में रोजगार और मूल्यवर्धन का आकलन

मुख्य निष्कर्षों का सारांश

INSTITUTE FOR HUMAN DEVELOPMENT
NEW DELHI • RANCHI
www.ihdindia.org

क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया

भारतीय शिल्प का अर्थशास्त्र

हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र में रोजगार और मूल्यवर्धन का आकलन

मुख्य निष्कर्षों का सारांश

2026

INSTITUTE FOR HUMAN DEVELOPMENT
NEW DELHI • RANCHI
www.ihdindia.org

क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया

इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट (आईएचडी)
256, दूसरी मंज़िल, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज-III
नई दिल्ली – 110020
फोन: +91 11 41064679, +91 9871177540
ईमेल: mail@ihdindia.org; वेबसाइट: www.ihdindia.org

क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया
GF, टेम्पल ट्रीज़ अपार्टमेंट्स,
37, वेंकटनारायण रोड, टी. नगर,
चेन्नई, तमिलनाडु – 600017
ईमेल: info@craftscouncilofindia.in
फ़ोन: +91-44-24341456 | +91 98405 41456
वेबसाइट: https://craftscouncilofindia.in/

कॉपीराइट ©: क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया

अनुशंसित उद्धरण

IHD-CCI (2026):
भारतीय शिल्प का अर्थशास्त्र
हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र में रोजगार तथा मूल्यवर्धन का आकलन

डिज़ाइन और रूपरेखा
एम. एस. आरज़ू, डैफोडिल ग्राफ़िक्स, दिल्ली
मोबाइल: 8368564419

आईएचडी (IHD) की मुख्य टीम

मुख्य शोधकर्ता एवं परियोजना प्रमुख

प्रो. जी.सी. मन्ना प्रोफेसर और पूर्व महानिदेशक, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार

मुख्य टीम सदस्य

डॉ. सुनील कुमार मिश्रा सीनियर फेलो

श्री विकास दुबे सीनियर रिसर्च एसोसिएट

श्री सुबोध कुमार सीनियर रिसर्च एसोसिएट

सलाहकार समिति

अध्यक्ष

प्रो. एस. आर. हाशिम पूर्व सदस्य-सचिव, योजना आयोग और पूर्व अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग

सह-अध्यक्ष

प्रोफेसर अशोक चटर्जी सलाहकार, क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया

सदस्य

प्रोफेसर अलख एन. शर्मा निदेशक, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट

श्री राकेश कुमार पूर्व महानिदेशक, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार

प्रोफेसर अरुप मित्रा प्रोफेसर, साउथ एशियाई यूनिवर्सिटी

सुश्री गीता राम अध्यक्ष एमेरिटस, क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया

सुश्री मंजरी निरुला क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया

सुश्री शिखा मुखर्जी क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया

विषय सूची (Contents)

v	आईएचडी (IHD) की मुख्य टीम
vii	प्रस्तावना
ix	भूमिका
xiii	आभार
xvii	संक्षिप्ताक्षर (Abbreviations)
xix	विवरण, आकृति, मानचित्र, फ़ोटोग्राफ़, बॉक्स और परिशिष्ट तालिकाएँ
1-20	कार्यकारी सारांश (Executive Summary)
21-32	अध्याय 1 परिचय
33-48	अध्याय 2 अध्ययन के उद्देश्य और शोधप्रणाली
49-114	अध्याय 3 सर्वेक्षण के निष्कर्ष
115-126	अध्याय 4 सारांश और आगे की राह
127-130	संदर्भ
131-335	परिशिष्ट

मुख्य निष्कर्षों का सारांश

भारत की हस्तनिर्मित शिल्प परंपरा हजारों वर्षों में विकसित कौशलता की एक अद्वितीय विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के 17 सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में से 11 लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप से हस्तशिल्प क्षेत्र से संबद्ध हैं। युगों से हमारे कारीगरों द्वारा निर्मित विविध हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं के जीवंत साक्ष्य रहे हैं।

इस क्षेत्र से संबंधित आधिकारिक आँकड़े सीमित हैं। छठी आर्थिक जनगणना (2013–14) में इस दिशा में एक प्रयास किया गया था, जिसमें प्रत्येक विनिर्माण इकाई से यह पूछा गया था कि क्या वह हथकरघा या हस्तशिल्प गतिविधियों से जुड़ी है। इस मद को शामिल किए जाने से इस क्षेत्र में संलग्न प्रतिष्ठानों की संख्या तथा उनमें नियोजित श्रमिकों की संख्या का एक प्रारंभिक अनुमान करना संभव हो सका।

इन सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट (IHD) ने भारत के क्राफ्ट्स काउंसिल के सहयोग से यह सर्वेक्षण किया। इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे—

- इस क्षेत्र में संलग्न इकाइयों और व्यक्तियों की संख्या का स्वतंत्र आकलन प्रस्तुत करना;
- मूल्यवर्धन में इस क्षेत्र के योगदान का आकलन करना; तथा
- हस्तनिर्मित क्षेत्र को भविष्य में राष्ट्रीय लेखा-प्रणाली में समुचित रूप से समाहित करने हेतु एक उपयुक्त कार्यप्रणाली का सुझाव देना।

प्राथमिक सर्वेक्षण का भौगोलिक विस्तार और नमूना आकार

प्राथमिक सर्वेक्षण पाँच राज्यों असम, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में संपन्न किया गया। इन राज्यों का चयन इस प्रकार किया गया कि एक ओर देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो, और दूसरी ओर छठी आर्थिक जनगणना (EC) के अनुसार हथकरघा हस्तशिल्प (HH) इकाइयों की संख्या की दृष्टि से इन राज्यों की सापेक्षिक महत्ता भी परिलक्षित हो।

यह सर्वेक्षण प्रत्येक राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में किया गया। इस उद्देश्य से प्रत्येक राज्य से 3 जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाला नमूना चुना गया। प्रत्येक चयनित जिले से 20 गाँव और 20 जनगणना प्रगणक खंड (Census Enumeration Blocks/ CEBs) का प्रतिनिधित्व करने वाला चयन किया गया। अंततः प्रत्येक चयनित गाँव/CEB से अधिकतम 10 हथकरघा हस्तशिल्प इकाइयों को सर्वेक्षण हेतु चुना गया। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप पाँचों राज्यों को मिलाकर ग्रामीण क्षेत्रों से 300 गाँवों में स्थित 2,503 HH इकाइयों तथा शहरी क्षेत्रों से 300 CEBs में स्थित 2,156 HH इकाइयों का चयन किया गया।

सर्वेक्षण में अपनाई गई HH इकाई / प्रतिष्ठान और श्रमिक की अवधारणा

हथकरघा उद्योग की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें हाथ से बुनाई की तकनीक का उपयोग होता है, जो प्रायः पारंपरिक करघों पर प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा संचालित की जाती है। इसी प्रकार, हस्तशिल्प गतिविधि को उन उत्पादों के निर्माण से संबद्ध माना गया, जो या तो पूर्णतः हाथ से अथवा औज़ारों की सहायता से निर्मित होते हैं और जिनमें कलात्मकता तथा सौंदर्यात्मकता का तत्व निहित होता है।

यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सर्वेक्षण में केवल हथकरघा हस्तशिल्प गतिविधियों के विनिर्माण घटक को शामिल किया गया। दूसरे शब्दों में, केवल वे व्यक्ति/इकाइयाँ सर्वेक्षण के दायरे में थीं जो हथकरघा या हस्तशिल्प उत्पादों के निर्माण में संलग्न थीं; केवल क्रय-विक्रय (व्यापार) करने वाली इकाइयों अर्थात जो केवल हथकरघा/हस्तशिल्प उत्पादों की खरीद-बिक्री में संलग्न थीं को सर्वेक्षण से बाहर रखा गया।

एक HH इकाई अथवा प्रतिष्ठान को ऐसी इकाई के रूप में परिभाषित किया गया, जो मुख्यतः विक्रय के उद्देश्य से हथकरघा या हस्तशिल्प उत्पादों के निर्माण में संलग्न हो। HH प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों की गणना करते समय नियोजित और अनियोजित दोनों प्रकार के सभी श्रमिकों को शामिल किया गया। इसमें प्रतिष्ठान के मालिक, मालिक के अन्य अवैतनिक पारिवारिक सदस्य, तथा अन्य सभी सहायक श्रमिक सम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त, वे व्यक्ति जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन-क्रिया में संलग्न न होकर प्रतिष्ठान की सहायक गतिविधियों जैसे कच्चे माल की खरीद, उत्पादों का विपणन/निपटान, लेखा-जोखा का संधारण आदि से जुड़े थे, उन्हें भी प्रतिष्ठान के श्रमिकों की श्रेणी में शामिल किया गया।

क्षेत्रीय सर्वेक्षण की अवधि

असम, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में प्राथमिक सर्वेक्षण दिसंबर 2023 से मार्च 2024 के बीच संपन्न किया गया। इसके बाद तमिलनाडु में जून से अगस्त 2024 के दौरान क्षेत्रीय सर्वेक्षण किया गया। अंततः उत्तर प्रदेश में नवंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच यह कार्य पूरा किया गया।

क्षेत्र का अनुमानित आकार

प्रत्येक राज्य के 3 जिलों से संकलित नमूना-आधारित आँकड़ों के आधार पर हथकरघा हस्तशिल्प HH क्षेत्र के आकार का आकलन तैयार किया गया। यह आकलन प्रत्येक राज्य के लिए प्रतिष्ठानों की संख्या तथा श्रमिकों की संख्या दोनों के संदर्भ में किया गया। इसके तहत चुने गए जिलों के लिए गाँव और शहर अलग-अलग करके अनुमान लगाए गए। साथ ही पूरे राज्य के लिए (यानी सभी जिलों को मिलाकर) कुल अनुमान भी तैयार किए गए।

कुछ प्रमुख अनुमान निम्नलिखित हैं—

- कुल प्रतिष्ठानों की संख्या (पाँचों राज्य मिलाकर): 34 लाख
- कुल अनुमानित रोजगार (पाँचों राज्य मिलाकर): 61 लाख
- अखिल भारतीय स्तर पर कुल प्रतिष्ठानों का प्रारंभिक अनुमान: 65 लाख
- अखिल भारतीय स्तर पर क्षेत्र में संलग्न कुल व्यक्तियों का प्रारंभिक अनुमान: 113 लाख

पाँचों राज्यों में अनुमानित 34 लाख इकाइयों में हथकरघा और हस्तशिल्प इकाइयों की संख्या लगभग समान पाई गई। इनमें लगभग 17.8 लाख इकाइयाँ हथकरघा क्षेत्र से संबंधित थीं, जबकि 16.1 लाख इकाइयाँ हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़ी थीं। रोजगार की दृष्टि से अनुमानित 61 लाख व्यक्तियों में लगभग 29.4 लाख लोग हथकरघा क्षेत्र में तथा 31.7 लाख लोग हस्तशिल्प क्षेत्र में संलग्न पाए गए। कुल हथकरघा हस्तशिल्प HH इकाइयों की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों की हिस्सेदारी (18.7 लाख इकाइयाँ) शहरी क्षेत्रों (15.2 लाख इकाइयाँ) की तुलना में कुछ अधिक पाई गई। हालाँकि, यह अनुपात विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न रहा।

कुल HH इकाइयों की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा, जहाँ इनकी अनुमानित संख्या 12.5 लाख थी। इसके बाद क्रमशः राजस्थान (8.5 लाख), पश्चिम बंगाल (7.4 लाख), तमिलनाडु (3.3 लाख) और असम (2.2 लाख) का स्थान रहा। श्रमिकों की संख्या के मामले में भी राज्यों की यही क्रम-स्थिति बनी रही। उत्तर प्रदेश में इस क्षेत्र में लगभग 22 लाख लोग संलग्न पाए गए, जबकि असम में यह संख्या 4.9 लाख रही। शेष तीन राज्यों में अनुमानित श्रमिक संख्या क्रमशः राजस्थान में 15.5 लाख, पश्चिम बंगाल में 12 लाख और तमिलनाडु में 6.7 लाख रही।

विनिर्माण उद्योग के भीतर इस क्षेत्र की अहमियत

असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASUSE) 2023–24 के अनुमानों की तुलना से स्पष्ट होता है कि इन पाँच राज्यों में विनिर्माण क्षेत्र के लगभग 42 प्रतिशत प्रतिष्ठान अर्थात लगभग प्रत्येक 10 में से 4 विनिर्माण प्रतिष्ठान हथकरघा हस्तशिल्प गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार, प्राथमिक सर्वेक्षण में HH क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या की तुलना आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) 2023–24 के विनिर्माण क्षेत्र संबंधी श्रम-आँकड़ों से करने पर यह तथ्य सामने आता है कि पाँचों राज्यों को मिलाकर विनिर्माण उद्योग में कार्यरत कुल श्रमिकों का लगभग 26 प्रतिशत हिस्सा HH क्षेत्र में कार्यरत है। दूसरे शब्दों में, विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत प्रत्येक 4 श्रमिकों में से 1 श्रमिक हथकरघा हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़ा है। यह अनुपात राजस्थान (43.8 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (35.4 प्रतिशत) और असम (33.8 प्रतिशत) में अपेक्षाकृत अधिक पाया गया, जबकि पश्चिम बंगाल (16.3 प्रतिशत) और तमिलनाडु (13.0 प्रतिशत) में यह अपेक्षाकृत कम रहा।

उपरोक्त तुलनात्मक विश्लेषण से यह निष्कर्ष निर्विवाद रूप से सामने आता है कि हथकरघा हस्तशिल्प (HH) क्षेत्र विनिर्माण उद्योग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सुदृढ़ घटक है।

प्रतिष्ठानों की कुछ प्रमुख विशेषताएँ

- अध्ययन से स्पष्ट होता है कि HH क्षेत्र के अधिकांश प्रतिष्ठान अत्यंत लघु स्वरूप के हैं। इनमें 56.6 प्रतिशत प्रतिष्ठान केवल 1 श्रमिक के साथ संचालित होते हैं, जबकि 28.2 प्रतिशत प्रतिष्ठानों में 2 श्रमिक कार्यरत हैं। इसके विपरीत, 5 से अधिक श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों की हिस्सेदारी अत्यंत सीमित लगभग 2.6 प्रतिशत पाई गई। इनमें 2 प्रतिशत प्रतिष्ठानों में 6 से 9 श्रमिक कार्यरत थे, जबकि केवल 0.6 प्रतिशत प्रतिष्ठान ऐसे थे जिनमें 10 या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत थे।
- सभी पाँचों राज्यों में लगभग शत-प्रतिशत प्रतिष्ठान स्वामित्वाधारित (proprietary) प्रकृति के पाए गए। अर्थात् यह क्षेत्र मुख्यतः व्यक्तिगत स्वामित्व और लघु पारिवारिक उद्यम की संरचना पर आधारित है।
- मालिकाना और साझेदारी वाले व्यवसायों में महिलाओं की हिस्सेदारी काफ़ी अधिक पाई गई। हथकरघा प्रतिष्ठानों में तमिलनाडु को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में महिलाओं का स्वामित्व अत्यंत महत्वपूर्ण स्तर पर दर्ज हुआ राजस्थान में 94.5 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 78.2 प्रतिशत, असम में 68.8 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में 47.9 प्रतिशत।
- हस्तशिल्प प्रतिष्ठानों में भी महिलाओं का मालिकाना हिस्सा उल्लेखनीय रहा विशेषतः उत्तर प्रदेश (65.1 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (49.5 प्रतिशत) और असम (44 प्रतिशत) में। यह तथ्य इस क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय आर्थिक भागीदारी और स्वामित्व-आधारित उपस्थिति को रेखांकित करता है।
- अध्ययन में यह भी पाया गया कि प्रत्येक राज्य में अधिकांश प्रतिष्ठान बारहमासी (perennial) प्रकृति के थे, अर्थात वे वर्ष के अधिकांश समय संचालित रहते हैं। यह निष्कर्ष इस धारणा को चुनौती देता है कि हथकरघा हस्तशिल्प क्षेत्र मुख्यतः मौसमी गतिविधि पर आधारित है। हालाँकि, असम में मौसमी प्रतिष्ठानों की हिस्सेदारी अपेक्षाकृत अधिक (20 प्रतिशत) पाई गई।
- घरेलू परिसर के भीतर संचालित प्रतिष्ठानों की संख्या अन्य प्रकार के प्रतिष्ठानों की तुलना में अधिक पाई गई। उत्तर प्रदेश में 97 प्रतिशत प्रतिष्ठान घरेलू परिसरों से संचालित होते पाए गए; असम और पश्चिम बंगाल में यह अनुपात लगभग 90 प्रतिशत

तथा राजस्थान में 72 प्रतिशत रहा। तमिलनाडु इस संदर्भ में एक उल्लेखनीय अपवाद के रूप में सामने आया, जहाँ अपेक्षाकृत कम लगभग 58 प्रतिशत प्रतिष्ठान घरेलू परिसरों के भीतर संचालित पाए गए।

- हथकरघा प्रतिष्ठानों का एक बड़ा हिस्सा अब भी किसी औपचारिक योजना, पंजीकरण व्यवस्था या संस्थागत कार्यक्रम के अंतर्गत दर्ज नहीं है। इसी प्रकार, हथकरघा हस्तशिल्प (HH) प्रतिष्ठानों में विधिवत लेखा-जोखा रखने की प्रवृत्ति भी अत्यंत सीमित पाई गई। इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल में ऐसे प्रतिष्ठानों का अनुपात सर्वाधिक (3.8 प्रतिशत) दर्ज हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश में यह सबसे कम (0.1 प्रतिशत) पाया गया। अधिकांश प्रतिष्ठानों ने बताया कि उनके यहाँ कार्यरत श्रमिकों ने अपना कौशल परंपरागत, वंशानुगत और जाति-आधारित ज्ञान-प्रणालियों के माध्यम से अर्जित किया है, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होती रही हैं। यह तथ्य इस क्षेत्र की गहरी सांस्कृतिक जड़ों और उसके जीवित ज्ञान-संस्कार की पुष्टि करता है।
- स्वामित्वाधारित और साझेदारी आधारित HH इकाइयों के स्वामियों में शिक्षा का स्तर सामान्यतः निम्न पाया गया। उत्तर प्रदेश में लगभग दो-तिहाई स्वामियों की शैक्षिक उपलब्धि प्राथमिक स्तर या उससे नीचे पाई गई। इसके बाद पश्चिम बंगाल और राजस्थान का स्थान रहा, जहाँ लगभग 60 प्रतिशत प्रतिष्ठान के मालिक इसी श्रेणी में आते हैं।
- उच्च माध्यमिक या उससे ऊपर की शिक्षा प्राप्त स्वामियों का अनुपात अत्यंत सीमित है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में यह केवल लगभग 7 प्रतिशत है; असम में 10 प्रतिशत; और तमिलनाडु में 13 प्रतिशत। तकनीकी शिक्षा की स्थिति भी इससे बहुत भिन्न नहीं है। अधिकांश राज्यों में प्रतिष्ठान-स्वामियों के बीच औपचारिक तकनीकी शिक्षा का स्पष्ट अभाव दिखाई देता है।
- हालाँकि, प्रतिष्ठान स्वामियों के कौशल का प्रमुख स्रोत औपचारिक प्रशिक्षण नहीं, बल्कि स्वदेशी, परंपरागत और वंशानुगत ज्ञान-संपदा ही पाई गई। राजस्थान (93 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (41 प्रतिशत), तमिलनाडु (37 प्रतिशत) और असम (36 प्रतिशत) में प्रतिष्ठान स्वामियों के कौशल का प्रमुख आधार यही परंपरागत/ वंशानुगत ज्ञान रहा। इस संदर्भ में पश्चिम बंगाल एक अपवाद के रूप में सामने आया, जहाँ यह अनुपात केवल 1 प्रतिशत दर्ज किया गया।

श्रमिकों का स्वरूप: कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

- हथकरघा हस्तशिल्प (HH) क्षेत्र में संलग्न अनुमानित 61 लाख श्रमिकों में नियोजित (hired) श्रमिकों की हिस्सेदारी प्रत्येक राज्य में अपेक्षाकृत कम पाई गई। यह अनुपात उत्तर प्रदेश में सबसे कम (5.2 प्रतिशत) तथा असम में सबसे अधिक (37.4 प्रतिशत) दर्ज किया गया। सामान्यतः शहरी क्षेत्रों में नियोजित श्रमिकों का अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक पाया गया।
- इस क्षेत्र की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता इसमें महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी है। अध्ययन में पाया गया कि कार्यबल का बड़ा हिस्सा महिलाओं का है। पाँचों राज्यों में उत्तर प्रदेश इस दृष्टि से सबसे आगे रहा, जहाँ 71.6 प्रतिशत श्रमिक महिलाएँ थीं। राजस्थान (62 प्रतिशत) और असम (57.4 प्रतिशत) ऐसे अन्य राज्य रहे, जहाँ कुल श्रमिकों में महिलाओं की हिस्सेदारी आधे से अधिक पाई गई। इसके विपरीत, तमिलनाडु में महिला श्रम-भागीदारी सबसे कम (32.5 प्रतिशत) दर्ज हुई। पश्चिम बंगाल में लगभग 47.8 प्रतिशत श्रमिक महिलाएँ थीं।
- अधिकांश प्रतिष्ठानों ने यह बताया कि उनके यहाँ कार्यरत श्रमिकों ने अपना कौशल पारंपरिक और परिवार से मिले ज्ञान से सीखा है। असम (91.1 प्रतिशत), तमिलनाडु (89.9 प्रतिशत) और राजस्थान (85.6 प्रतिशत) में उल्लेखनीय संख्या में प्रतिष्ठानों ने यह संकेत दिया कि उनके श्रमिकों का कौशल मुख्यतः इसी परंपरागत ज्ञान-व्यवस्था से विकसित हुआ है।
- समग्र रूप से देखें तो औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त बुनकरों और शिल्पकारों का अनुपात अब भी अत्यंत सीमित है। इससे साफ होता है कि इस क्षेत्र में काम आज भी ज़्यादातर पुरानी परंपराओं, अनुभव से सीखी गई ट्रेनिंग और समुदाय से सीखे गए हुनर पर चलता है।

निर्मित उत्पादों के प्रमुख प्रकार

हथकरघा हस्तशिल्प (HH) प्रतिष्ठानों द्वारा निर्मित उत्पादों का स्वरूप राज्य-विशेष की शिल्प परंपराओं, स्थानीय संसाधनों, सांस्कृतिक विशिष्टताओं और बाज़ार की माँग के अनुसार भिन्न-भिन्न पाया गया। विभिन्न राज्यों में निर्मित प्रमुख उत्पादों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

कच्चे माल की प्राप्ति और उत्पादों के विपणन के स्रोत

कच्चे माल की प्राप्ति के स्रोतों जैसे 'खुला बाज़ार', 'उस्ताद बुनकर/ ठेकेदार/ इनपुट आपूर्तिकर्ता', 'आयात', 'सहकारी समिति', 'नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड/ स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड' तथा 'केवीआईसी/ केवीआईबी' में से 99 प्रतिशत लगभग हथकरघा हस्तशिल्प (HH) प्रतिष्ठान मुख्यतः पहले दो स्रोतों पर निर्भर पाए गए। अर्थात कच्चे माल की उपलब्धता का आधार लगभग पूरी तरह खुला बाज़ार और ठेकेदार/ उस्ताद-आधारित आपूर्ति तंत्र है।

हथकरघा इकाइयों में, पिछले 365 दिनों के दौरान कच्चे माल की कुल खरीद के मूल्य के आधार पर, असम में खुला बाज़ार कच्चे माल का सबसे प्रमुख स्रोत पाया गया, जहाँ 80 प्रतिशत से अधिक इकाइयों ने अपने अधिकांश कच्चे माल की प्राप्ति इसी माध्यम से की। इसके विपरीत, शेष राज्यों में उस्ताद बुनकर / ठेकेदार / इनपुट आपूर्तिकर्ता कच्चे माल का सबसे प्रमुख स्रोत रहे (राजस्थान में 92.1 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 97.2 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 72.6 प्रतिशत और तमिलनाडु में 61.9 प्रतिशत)। इकाइयाँ मुख्यतः इसी स्रोत पर निर्भर पाई गईं। हस्तशिल्प इकाइयों के मामले में उत्तर प्रदेश एक अपवाद के रूप में सामने आया, जहाँ उस्ताद बुनकर / ठेकेदार / इनपुट आपूर्तिकर्ता (77.8 प्रतिशत)

तालिका 1: राज्यों में हथकरघा और हस्तशिल्प इकाइयों के प्रमुख उत्पाद

राज्य	निर्मित प्रमुख उत्पाद (प्रतिष्ठानों का अनुपात)
हथकरघा इकाइयाँ	
असम	मेखला-चादर/साड़ी (53.4 प्रतिशत); तौलिया/धोती (30.9 प्रतिशत); बुनाई/कताई (4.7 प्रतिशत); रेशमी/प्लास्टिक चादर (3.3 प्रतिशत); सूती बेडशीट (3.2 प्रतिशत)
राजस्थान	बंधेज कार्य (85.2 प्रतिशत); साड़ी पर गोटा-पट्टी लगाने का कार्य (4.2 प्रतिशत); कालीन (2.5 प्रतिशत)
तमिलनाडु	साड़ी (81.1 प्रतिशत); गमछा/धोती (9.3 प्रतिशत); कढ़ाई कार्य (3.7 प्रतिशत); फर्श अथवा द्वार-चटाई (1.7 प्रतिशत); कालीन (1.7 प्रतिशत)
उत्तर प्रदेश	कढ़ाई कार्य (44.9 प्रतिशत); अन्य हथकरघा उत्पाद (11.7 प्रतिशत); जरी कार्य (11.2 प्रतिशत); साड़ी (10.8 प्रतिशत); कालीन (6.7 प्रतिशत); धागा (6.0 प्रतिशत)
पश्चिम बंगाल	जरी कार्य (64.5 प्रतिशत); साड़ी (26.8 प्रतिशत), ऊन के उत्पाद (1.8 प्रतिशत); गमछा/धोती (1.6 प्रतिशत)
हस्तशिल्प इकाइयाँ	
असम	बाँस और बेंत के उत्पाद (67.8 प्रतिशत); लकड़ी के उत्पाद (18.4 प्रतिशत); मिट्टी के उत्पाद (5.1 प्रतिशत); धातु के उत्पाद (2.7 प्रतिशत)
राजस्थान	लकड़ी के उत्पाद (28.2 प्रतिशत); मिट्टी के उत्पाद (20.5 प्रतिशत); धातु के उत्पाद (18.0 प्रतिशत); जूते (10.7 प्रतिशत); मूर्तियाँ (5.7 प्रतिशत); चूड़ियों पर पत्थर जड़ने का कार्य (4.5 प्रतिशत); लाख की चूड़ियाँ (4.3 प्रतिशत)
तमिलनाडु	पत्तल/पत्ते की प्लेट निर्माण (25.6 प्रतिशत); धातु उत्पाद (17.8 प्रतिशत); तार-आधारित उत्पाद (15.9 प्रतिशत); लकड़ी के उत्पाद (14.0 प्रतिशत); बाँस और बेंत के उत्पाद (7.1 प्रतिशत); मिट्टी के उत्पाद (6.2 प्रतिशत)
उत्तर प्रदेश	मोती की माला/कंगन (47.7 प्रतिशत); जूते (15.3 प्रतिशत); लकड़ी के उत्पाद (9.8 प्रतिशत); मिट्टी के उत्पाद (7.6 प्रतिशत); धातु के उत्पाद (6.7 प्रतिशत); सजावटी वस्तुएँ (3.1 प्रतिशत); चूड़ियों पर पत्थर जड़ने का कार्य (2.9 प्रतिशत)
पश्चिम बंगाल	कागज़ के उत्पाद (30.8 प्रतिशत); राखी (15.8 प्रतिशत); धातु उत्पाद (11.4 प्रतिशत); मूर्तियाँ (11.0 प्रतिशत); लकड़ी के उत्पाद (10.8 प्रतिशत); बाँस और बेंत के उत्पाद (8.2 प्रतिशत); मिट्टी के उत्पाद (6.8 प्रतिशत)

कच्चे माल के प्रमुख आपूर्तिकर्ता थे। इसके विपरीत, अन्य राज्यों में खुला बाज़ार ही कच्चे माल का प्रमुख स्रोत रहा: असम (91.2 प्रतिशत), तमिलनाडु (85.8 प्रतिशत), राजस्थान (74.5 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (72.0 प्रतिशत)।

उत्पादों के विपणन/निपटान (disposal of products) की स्थिति भी अधिकांशतः इसी पैटर्न का अनुसरण करती है। स्थानीय बाज़ार, उस्ताद बुनकर/ ठेकेदार/ इनपुट आपूर्तिकर्ता, तथा (केवल हथकरघा इकाइयों के मामले में) सहकारी समितियाँ उत्पादों के निपटान के प्रमुख माध्यम पाए गए। उत्पादों के निर्यात की उपस्थिति अत्यंत सीमित और विरल पाई गई। निर्यात के उदाहरण केवल कुछ विशिष्ट मामलों में दर्ज हुए जयपुर और बरेली के प्रत्येक जिले में केवल 0.1 प्रतिशत हथकरघा इकाइयों में; जयपुर जिले की 0.3 प्रतिशत हस्तशिल्प इकाइयों में; तथा सलेम जिले की 4.4 प्रतिशत हस्तशिल्प इकाइयों में।

संगठित मेलों, प्रदर्शनियों, हाटों अथवा स्टॉलों के माध्यम से उत्पादों के विपणन की सूचना देने वाले प्रतिष्ठानों का अनुपात भी अत्यंत सीमित पाया गया। यह प्रतिशत इस प्रकार था हथकरघा इकाइयाँ: असम (5.6 प्रतिशत), तमिलनाडु (0.2 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (0.2 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (0.3 प्रतिशत)। हस्तशिल्प इकाइयाँ: असम (9.4 प्रतिशत), राजस्थान (0.3 प्रतिशत), तमिलनाडु (0.8 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (0.3 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (0.7 प्रतिशत)।

यह निष्कर्ष उस प्रचलित धारणा को चुनौती देता है कि शिल्प-क्षेत्र की विपणन-व्यवस्था मुख्यतः मेलों, प्रदर्शनियों और हस्तशिल्प आयोजनों पर निर्भर है। वस्तुतः, इस क्षेत्र की वास्तविक विपणन-संरचना अधिकतर स्थानीय, अनौपचारिक और मध्यस्थ-आधारित तंत्र पर टिकी हुई है।

प्रमुख समस्याएँ, बकाया ऋण और व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम

हथकरघा हस्तशिल्प (HH) प्रतिष्ठानों द्वारा जिन प्रमुख समस्याओं की पहचान की गई, उनमें बाज़ार तक सीमित पहुँच और वित्तीय बाधाएँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहीं। अधिकांश राज्यों में 50 प्रतिशत से अधिक प्रतिष्ठानों ने बाज़ार-सुलभता की कमी तथा ऋण प्राप्त करने में कठिनाई जैसी वित्तीय समस्याओं को प्रमुख अवरोध के रूप में रेखांकित किया। उत्तर प्रदेश इस संदर्भ में एक आंशिक अपवाद रहा, जहाँ वित्तीय कठिनाइयों की शिकायत अपेक्षाकृत कम (36 प्रतिशत) दर्ज की गई। कच्चे माल से संबंधित समस्याएँ विशेषतः उसकी कीमत और उपलब्धता भी लगभग सभी राज्यों में एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आईं।

प्रत्येक राज्य में कम-से-कम 40 प्रतिशत प्रतिष्ठानों ने इसे एक प्रमुख समस्या बताया। इसके अतिरिक्त, बड़ी संख्या में प्रतिष्ठानों ने जिन अन्य महत्वपूर्ण बाधाओं का उल्लेख किया, उनमें कारखाना-आधारित/आयातित बड़े पैमाने के उत्पादन से प्रतिस्पर्धा, कार्य-स्थल की कमी, तथा प्रशिक्षित/कुशल श्रमिकों का अभाव प्रमुख रहे।

डिज़ाइन और उत्पादों की नकल से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा भी एक उल्लेखनीय समस्या के रूप में सामने आई। राजस्थान (23.4 प्रतिशत) और असम (12.1 प्रतिशत) में उल्लेखनीय संख्या में प्रतिष्ठानों ने इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा को गंभीर चुनौती के रूप में रेखांकित किया। सर्वेक्षण के समय बकाया ऋण (outstanding loan) की उपस्थिति भी कुछ राज्यों में उल्लेखनीय रूप से दर्ज की गई। तमिलनाडु (12.1 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (10.9 प्रतिशत) में 10 प्रतिशत से अधिक (HH) प्रतिष्ठानों ने बताया कि उन पर सर्वेक्षण के समय ऋण बकाया था। अन्य राज्यों में यह अनुपात अपेक्षाकृत कम रहा असम में 5.3 प्रतिशत, राजस्थान में 2.1 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में मात्र 0.2 प्रतिशत ।

व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिम (occupational health risks) की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे अधिक संवेदनशील राज्य के रूप में सामने आया, जहाँ 45 प्रतिशत (HH) प्रतिष्ठानों ने इस प्रकार के जोखिमों की सूचना दी। इसके बाद पश्चिम बंगाल (23.2 प्रतिशत), तमिलनाडु (17 प्रतिशत), असम (15.4 प्रतिशत) और राजस्थान (3.7 प्रतिशत) का स्थान रहा। अधिकांश राज्यों में हस्तशिल्प प्रतिष्ठानों ने हथकरघा इकाइयों की तुलना में व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों की अधिक सूचना दी। इससे स्पष्ट है कि शिल्पगत श्रम की प्रकृति अनेक स्तरों पर शारीरिक जोखिमों से जुड़ी हुई है।

यह अध्ययन बताता है कि काम से जुड़ी सेहत और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे अब इस क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी और तुरंत ध्यान देने वाले बन गए हैं। यदि इस क्षेत्र में प्रतिभा को बनाए रखना है और नई पीढ़ियों को आकर्षित करना है, तो इन दोनों प्रश्नों को प्राथमिकता के साथ संबोधित करना अनिवार्य होगा।

प्रतिष्ठानों की वर्तमान स्थिति

सर्वेक्षण में हथकरघा–हस्तशिल्प (HH) प्रतिष्ठानों की वर्तमान स्थिति का आकलन दो समय-फलक पर किया गया पहला, पिछले 10 वर्षों की तुलना में; और दूसरा, कोविड-पूर्व अवधि की तुलना में। दोनों ही संदर्भों में एक स्पष्ट प्रवृत्ति सामने आती है : अधिकांश राज्यों में उत्पादन के वर्तमान स्तर में गिरावट दर्ज करने वाले प्रतिष्ठानों का अनुपात, वृद्धि दर्ज करने वाले प्रतिष्ठानों की तुलना में सामान्यतः अधिक है। यह निष्कर्ष इस क्षेत्र की संरचनात्मक चुनौतियों और उसके विकास-पथ में उपस्थित अवरोधों को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। (देखें तालिका)

समग्र रूप से कहा जा सकता है कि प्रत्येक राज्य में हथकरघा हस्तशिल्प (HH) प्रतिष्ठानों के बहुमत ने पिछले दस वर्षों की अवधि में, तथा कोविड-पूर्व स्थिति की तुलना में, उत्पादन के स्तर में या तो ठहराव अथवा गिरावट की सूचना दी। विशेष रूप से तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में पिछले दस वर्षों के दौरान वृद्धि दर्ज करने वाले प्रतिष्ठानों का अनुपात अत्यंत कम 10 प्रतिशत से भी नीचे पाया गया।

सकल मूल्य वर्धन (GVA) में योगदान तथा प्रति प्रतिष्ठान/ प्रति श्रमिक GVA

सकल मूल्य वर्धन (Gross Value Added / GVA) किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का एक प्रमुख आधारभूत घटक है। राष्ट्रीय स्तर पर कुल GVA, सभी प्रतिष्ठानों द्वारा सृजित GVA के योग से निर्मित

तालिका 2: हथकरघा और हस्तशिल्प प्रतिष्ठानों की वर्तमान स्थिति

राज्य	प्रतिष्ठानों का अनुपात			
	पिछले 10 वर्षों की स्थिति		कोविड-पूर्व अवधि की तुलना में वर्तमान स्थिति	
	वृद्धि	गिरावट	वृद्धि	गिरावट
हथकरघा इकाइयाँ				
असम	12.9	50.4	11.5	55.1
राजस्थान	32.1	30.0	15.9	17.4
पश्चिम बंगाल	32.6	48.0	39.9	44.5
तमिलनाडु	2.1	66.3	2.1	65 2
उत्तर प्रदेश	8.1	51.4	20.9	31.8
हस्तशिल्प इकाइयाँ				
असम	21.5	53.7	13.5	57.3
राजस्थान	24.8	24.7	4.3	27.8
पश्चिम बंगाल	17.4	36.3	24.8	33.0
तमिलनाडु	8.5	27.6	7.8	28.4
उत्तर प्रदेश	7.3	38.2	28.5	28.1

होता है। सैद्धांतिक रूप से किसी एक प्रतिष्ठान का GVA उस प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिकों को दिए गए पारिश्रमिक, प्रतिष्ठान द्वारा अर्जित आय, तथा (जहाँ लागू हो) भूमि के किराये और ऋण पर देय ब्याज के कुल योग से निर्मित होता है।

तालिका 3 में यह देखा जा सकता है कि पाँचों राज्यों के हथकरघा हस्तशिल्प प्रतिष्ठानों ने मिलकर वार्षिक रूप से लगभग 51,445 करोड़ रुपये का सकल मूल्य वर्धन (GVA) सृजित किया। इस आकलन के लिए संदर्भ अवधि दो प्रकार की रही जिन प्रतिष्ठानों में विधिवत लेखा-जोखा उपलब्ध था, उनके लिए सर्वेक्षण-तिथि से पूर्व का अंतिम लेखा-वर्ष; और जिन प्रतिष्ठानों में लेखा-जोखा उपलब्ध नहीं था, उनके लिए सर्वेक्षण-तिथि से पूर्व के अंतिम 365 दिन। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए विनिर्माण क्षेत्र के कुल सकल राज्य मूल्य वर्धन (Gross State Value Added / GSVA) की तुलना में HH क्षेत्र का योगदान इस प्रकार पाया गया असम : 9.6 प्रतिशत, राजस्थान : 9.9 प्रतिशत, तमिलनाडु : 0.9 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश : 3.6 प्रतिशत एवं पश्चिम बंगाल : 6.8 प्रतिशत।

ये आँकड़े स्पष्ट करते हैं कि हथकरघा हस्तशिल्प क्षेत्र, आकार में बिखरा और संरचनात्मक रूप से लघु होने के बावजूद, विनिर्माण अर्थव्यवस्था में मूल्यवर्धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विशेष रूप से असम और राजस्थान जैसे राज्यों में इसका योगदान अत्यंत उल्लेखनीय है, जहाँ यह क्षेत्र विनिर्माण-आधारित राज्य अर्थव्यवस्था के भीतर एक सशक्त उत्पादक उपस्थिति दर्ज करता है।

वार्षिक सकल मूल्य वर्धन (GVA) प्रति श्रमिक के आधार पर पाँचों राज्यों का औसत लगभग 84,000 रुपये प्रतिवर्ष पाया गया। राज्यों के बीच इसमें उल्लेखनीय अंतर दिखाई देता है। पश्चिम बंगाल में प्रति श्रमिक वार्षिक GVA सर्वाधिक, लगभग 1.25 लाख रुपये दर्ज किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश में यह सबसे कम, लगभग 44,000 रुपये प्रति श्रमिक प्रतिवर्ष पाया गया। यदि इसे मासिक औसत में रूपांतरित करें, तो पाँचों राज्यों का औसत लगभग 7,000 रुपये प्रति माह बैठता है। दैनिक औसत के रूप में यह लगभग 270 रुपये प्रतिदिन होता है (यह मानते हुए कि एक श्रमिक महीने में 26 दिन कार्य करता है और 4 दिन विश्राम करता है)। यह राशि निर्धारित दैनिक न्यूनतम मजदूरी से स्पष्ट रूप से कम है। यह तथ्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्षेत्र उच्च कौशल, गहन श्रम, परंपरागत दक्षता और दीर्घ अभ्यास की माँग करता है, किंतु उसके प्रतिफल के रूप में प्राप्त आय न्यूनतम श्रम-मानकों से भी नीचे बनी हुई है।

इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि हथकरघा हस्तशिल्प क्षेत्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय मूल्यवर्धन करता है, किंतु इस मूल्यवर्धन का लाभ श्रमिक आय के रूप में पर्याप्त रूप से परिलक्षित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, यह क्षेत्र उत्पादक तो है, परंतु प्रतिफल की दृष्टि से अब भी गहरे असंतुलन का शिकार है।

नीतिगत निहितार्थ

भारत का हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र केवल देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संवाहक भर नहीं है, बल्कि यह करोड़ों लोगों विशेषतः वंचित, हाशिये पर स्थित और सामाजिक रूप से संवेदनशील समुदायों की आजीविका का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार भी है।

इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अत्यंत उल्लेखनीय है। बड़ी संख्या में महिलाएँ घरेलू व्यय वहन करने और परिवार की आय में योगदान देने के लिए इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। इस प्रकार, यह क्षेत्र केवल उत्पादन का नहीं, बल्कि घरेलू अर्थव्यवस्था, स्त्री-आर्थिक भागीदारी और सामुदायिक स्थिरता का भी एक महत्वपूर्ण आधार है। इसके बावजूद, आजीविका के इस महत्वपूर्ण स्रोत को अनेक संरचनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें श्रमिकों की निम्न आय, बाज़ार तक सीमित पहुँच, तथा प्रतिष्ठानों के दैनिक संचालन में आने वाली विविध बाधाएँ प्रमुख हैं।

सर्वेक्षण में सरकारी सहायता योजनाओं के सीमित उपयोग के निष्कर्ष को देखते हुए यह स्पष्ट है कि विभिन्न मंत्रालयों विशेषतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), वस्त्र मंत्रालय, तथा संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित योजनाओं के प्रति व्यापक जागरूकता पैदा करने और उनके बेहतर समेकन की आवश्यकता है। इस संदर्भ में वीवर सर्विस सेंटर (Weaver Service Centres), हस्तशिल्प एवं हथकरघा क्लस्टरों, सहकारी समितियों तथा स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है।

अध्ययन यह भी रेखांकित करता है कि बड़ी संख्या में कारीगर अब भी केवल पारंपरिक तकनीकों पर निर्भर हैं, जिसके कारण उनके उत्पादों का बाज़ार-मूल्य अक्सर सीमित रह जाता है। इस स्थिति से निपटने के लिए आधुनिक डिज़ाइन, उत्पाद-विकास और पर्यावरण-अनुकूल उत्पादन तकनीकों में निरंतर कौशल-विकास (up-skilling) और प्रशिक्षण की आवश्यकता है। कारीगर उत्पादों के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों

तालिका 3: हथकरघा और हस्तशिल्प इकाइयों द्वारा अनुमानित वार्षिक कुल और GVA, प्रति HH इकाई GVA और प्रति श्रमिक GVA

राज्य	अनुमानित वार्षिक GVA (रु. लाख)	प्रति HH प्रतिष्ठान वार्षिक GVA (रु.)	प्रति श्रमिक वार्षिक GVA (रु.)
असम	5,72,721	2,59,571	1,16,417
राजस्थान	16,81,608	1,97,806	1,08,361
तमिलनाडु	4,15,997	1,27,400	62,519
उत्तर प्रदेश	9,71,951	77,844	44,210
कुल	51,44,515	1,51,850	84,207

स्तरों पर बाज़ार तक पहुँच का विस्तार भी अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, प्रदर्शनियाँ, और क्रेता विक्रेता संवाद (buyer-seller meets) महत्वपूर्ण माध्यम बन सकते हैं। इसके साथ ही, वित्तीय सहायता, ऋण और बीमा तक पहुँच में मौजूद प्रशासनिक अवरोधों को कम करना भी क्षेत्रीय विकास के लिए अनिवार्य है।

अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि कच्चे माल, वित्तीय संसाधनों और सामाजिक सुरक्षा तक बेहतर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए नई योजनाओं का निर्माण और प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है। चूँकि हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र करोड़ों लोगों विशेषतः महिलाओं, वंचित समुदायों और हाशिये पर स्थित समूहों की आजीविका का आधार है, इसलिए इस क्षेत्र के लिए नीतिगत हस्तक्षेप को केवल आर्थिक प्रोत्साहन के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक संरक्षण और समावेशी विकास की व्यापक परियोजना के रूप में देखा जाना चाहिए।

पिछले एक दशक में इस क्षेत्र ने कोविड-19, विमुद्रीकरण, जीएसटी संबंधी जटिलताओं और बाज़ार के उतार-चढ़ाव जैसी अनेक प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया है। इसके बावजूद, दस वर्ष पूर्व की स्थिति तथा कोविड-पूर्व अवधि की तुलना में उत्पादन-स्तर में गिरावट दर्ज करने वाले प्रतिष्ठानों का अनुपात चिंताजनक रूप से ऊँचा बना हुआ है। इस स्थिति से निपटने के लिए त्वरित और लक्षित नीतिगत हस्तक्षेप अनिवार्य हैं।

सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि बड़ी संख्या में प्रतिष्ठान कच्चे माल की आपूर्ति के लिए तथा तैयार उत्पादों के विपणन/निपटान के लिए उस्ताद बुनकरों, ठेकेदारों और इनपुट आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर हैं। इस तथ्य को देखते हुए, यदि शिल्प-उस्तादों और मास्टर कारीगरों की भूमिका को प्रमुख प्रशिक्षक, मार्गदर्शक और ज्ञान-संरक्षक के रूप में संस्थागत मान्यता और सुदृढ़ समर्थन दिया जाए, तो इससे क्षेत्र की संरचनात्मक मजबूती में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। प्रौद्योगिकी और डिज़ाइन संस्थानों को भी इस प्रक्रिया में उनकी भूमिका को सशक्त बनाने के लिए सक्रिय रूप से जोड़ा जाना चाहिए।

उद्यमिता-आधारित प्रशिक्षण संस्थानों और उच्च शिक्षा प्रणालियों के माध्यम से युवाओं को शिल्पगत गतिविधियों से जोड़ना भी इस क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। इससे न केवल नई पीढ़ी का जुड़ाव बढ़ेगा, बल्कि शिल्प को एक व्यवहार्य, सम्मानजनक और नवोन्मेषी आजीविका विकल्प के रूप में भी स्थापित किया जा सकेगा। अध्ययन यह भी बताता है कि बड़ी संख्या में प्रतिष्ठान के मालिक अब भी सरकारी सहायता योजनाओं के प्रति पर्याप्त रूप से जागरूक नहीं हैं। इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र और नागरिक समाज के बीच अधिक सशक्त साझेदारी विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि जागरूकता अभियानों को तेज किया जा सके और स्थानीय स्तर पर निगरानी एवं पहुँच-सुनिश्चितता को मजबूत बनाया जा सके।

मेलों, प्रदर्शनियों, हाटों और अन्य विपणन आयोजनों में कारीगरों की सीमित भागीदारी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में सामने आई है। इसे दूर करने के लिए प्रचार, जागरूकता और संस्थागत सहयोग के माध्यम से कारीगरों की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। सामाजिक सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण भी इस क्षेत्र की स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रतिभा को बनाए रखने और नई पीढ़ी को आकर्षित करने के लिए स्वास्थ्य, पेंशन और समग्र कल्याण से जुड़ी योजनाओं का विस्तार अपरिहार्य है। इसके लिए अन्य क्षेत्रों और संस्थागत तंत्रों के साथ साझेदारी विकसित कर व्यापक सामाजिक सुरक्षा ढाँचा निर्मित करना समय की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है।

आगे के सर्वेक्षणों की आवश्यकता

संसाधनों की सीमाओं के कारण यह अध्ययन पाँच राज्यों तक सीमित रहा और इसके नमूना-आकार पर भी स्वाभाविक सीमाएँ रहीं। फिर भी, इस अध्ययन ने क्षेत्र की कार्यप्रणाली, उसके वास्तविक आकार, उत्पादन-संरचना, आजीविका-आधार और उसके समक्ष उपस्थित चुनौतियों के बारे में अनेक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियाँ उपलब्ध कराई हैं। विस्तृत और अधिक समग्र समझ विकसित करने के लिए, तथा 2013–14 की आर्थिक गणना (Economic Census) की अनुशंसाओं के अनुरूप हस्तनिर्मित क्षेत्र को राष्ट्रीय लेखा-प्रणाली में व्यवस्थित रूप से एकीकृत करने की दिशा में, यह आवश्यक होगा कि वर्तमान अध्ययन की पद्धति को अधिक राज्यों में दोहराया जाए और आगे चलकर इसे अखिल-भारतीय (pan-India) सर्वेक्षण के रूप में विस्तारित किया जाए।

ऐसी पहल के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (MoSPI), वस्त्र मंत्रालय (MoT) विशेषतः हथकरघा और हस्तशिल्प विकास आयुक्त कार्यालयों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय जैसे संबंधित मंत्रालयों के साथ नियमित संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त, उद्योग संगठनों और अन्य हितधारकों के साथ साझेदारी भी आवश्यक होगी, ताकि हथकरघा हस्तशिल्प क्षेत्र का एक अधिक व्यापक, विश्वसनीय और अद्यतन डाटाबेस विकसित किया जा सके।

राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रतिष्ठानों के व्यापक सर्वेक्षण इस क्षेत्र की आधारभूत संरचना, कौशल विकास, बाज़ार तक पहुँच और प्रौद्योगिकी अनुकूलन से जुड़ी कमियों की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। ऐसे सर्वेक्षण लक्षित नीतियों, वित्तीय सहायता और कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण के लिए ठोस साक्ष्य भी उपलब्ध कराएँगे, जिससे कारीगरों की आजीविका को अधिक सुदृढ़ और टिकाऊ बनाया जा सके। नियमित अंतराल पर किए जाने वाले सर्वेक्षण समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को भी दर्ज कर सकेंगे। इससे राज्य और केंद्र दोनों स्तरों की सरकारों को ऐसी नीतियाँ और रणनीतियाँ विकसित करने में सहायता मिलेगी, जो इस क्षेत्र के सतत विकास, सामाजिक स्थिरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ कर सकें।

राज्यवार फील्ड पर्यवेक्षक और अन्वेषक सूची

असम टीम

श्री रितामोनी सैकिया (समन्वयक पर्यवेक्षक)
सुश्री डेज़ी रहमान
सुश्री आस्था डोराडी बोरा
श्री जॉनी बरुवा
श्री जह्नु दत्ता
श्री चिन्मय पाठक
सुश्री ममोनी मंकी
सुश्री रुपज्योति सैकिया
सुश्री मृन्मोयी कोंवर
सुश्री ऋतु उरंग

राजस्थान टीम

श्री जसवंत राव (समन्वयक पर्यवेक्षक)
श्री सत्यपाल सिंह (समन्वयक पर्यवेक्षक)
श्री बलवंत राव गौतम
श्री रोहित कुमार सिंह
श्री हनुमान प्रसाद शर्मा
श्री अमित कुमार चौबे
श्री दिलराज मीना
सुश्री अल्का कुमारी
सुश्री संध्या गुप्ता
सुश्री मेनिका भारती
सुश्री किरण गुप्ता

पश्चिम बंगाल टीम

स्व. श्री श्रीनिवास पांडे (समन्वयक पर्यवेक्षक)
स्व. श्री देबाशीष रॉय (समन्वयक पर्यवेक्षक)
सुश्री अंजलि सोरेन
सुश्री साधना रॉय
श्री शुभा मंडल
सुश्री प्रीथा बिस्वास
सुश्री कबीता मंडल
श्री भोला नाथ घोष
श्री स्वरूप मंडल
श्री अमित कुमार बिस्वास
श्री श्रीकांत खानरा
श्री आशीष बेड़ा

तमिलनाडु टीम

डॉ. पी. चंद्रन (समन्वयक पर्यवेक्षक)
डॉ. एम. रेक्स सहायराज (समन्वयक पर्यवेक्षक)
श्री एस. वेट्रिवेल (समन्वयक पर्यवेक्षक)
सुश्री एस. भारती प्रियंका
सुश्री पार्कवी
सुश्री एम. बरनी
श्री के. उदय कुमार
डॉ. आई. कोकिला
श्री ए. कृष्णन
श्री सी. प्रभु
श्री अधित्यन अभिमन्यु टी. यू.
श्री भरत कुमार वी.
श्री दिनेश
सुश्री ए. मारिया प्रीथी
सुश्री अभिथा एस.
सुश्री पूजा एस.
सुश्री पी. शुभाश्री
सुश्री सिवलिनी ए. पी.
सुश्री सौम्या शिवकुमार
सुश्री सुवेथा एम. पी.
सुश्री विगासिनी सक्थिवेल

उत्तर प्रदेश टीम

श्री जसवंत राव (समन्वयक पर्यवेक्षक)
श्री सत्यपाल सिंह (समन्वयक पर्यवेक्षक)
श्री बलवंत राव गौतम
श्री रोहित कुमार सिंह
श्री अमित कुमार चौबे
सुश्री प्रियंका सिंघानिया
श्री राहुल कुमार सिंह
सुश्री मुनिता
सुश्री के. एम. रिंकी
सुश्री नादिया परवीन
सुश्री अंजलि तिवारी
श्री आशु खान

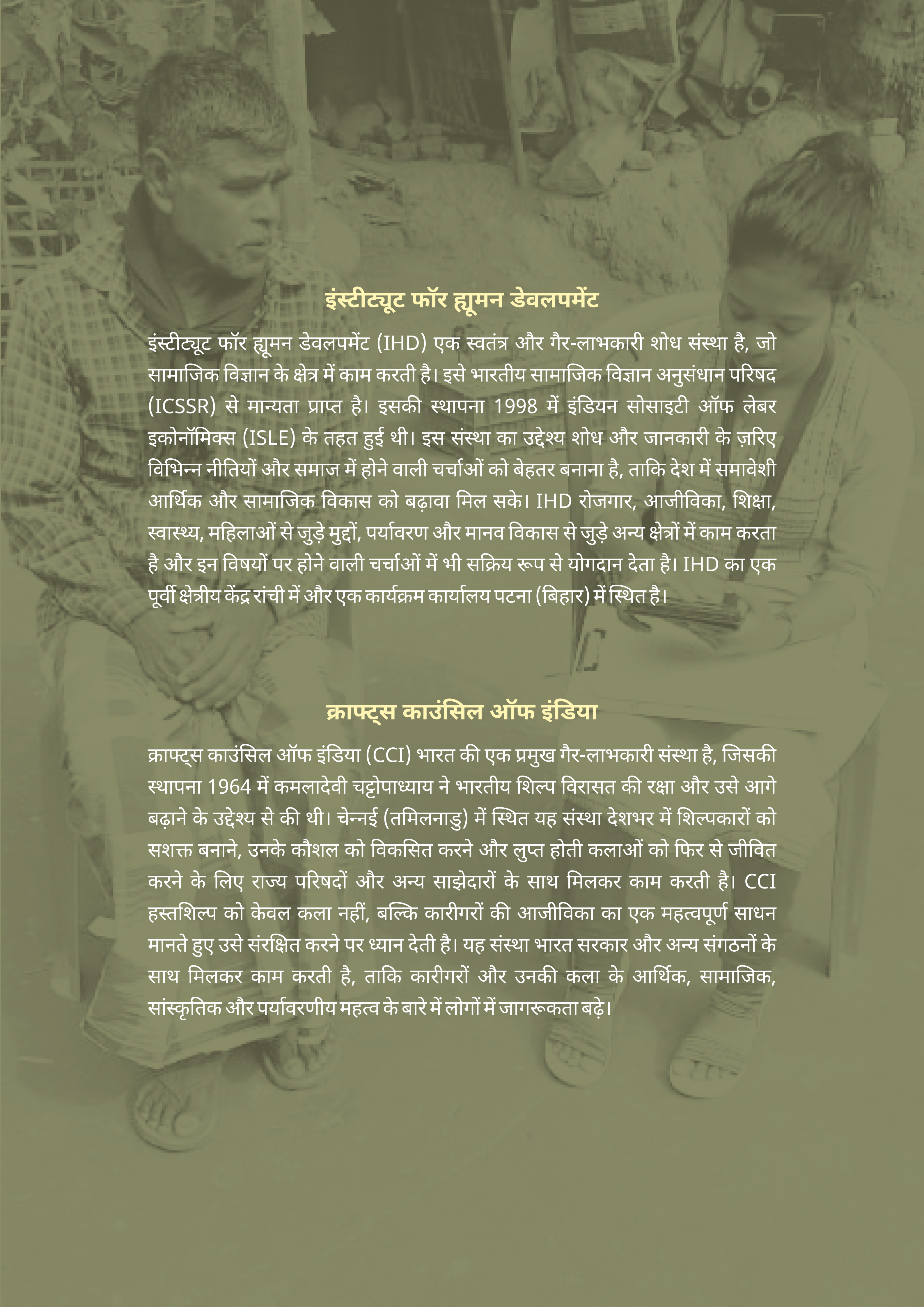

इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट

इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट (IHD) एक स्वतंत्र और गैर-लाभकारी शोध संस्था है, जो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में काम करती है। इसे भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) से मान्यता प्राप्त है। इसकी स्थापना 1998 में इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स (ISLE) के तहत हुई थी। इस संस्था का उद्देश्य शोध और जानकारी के ज़रिए विभिन्न नीतियों और समाज में होने वाली चर्चाओं को बेहतर बनाना है, ताकि देश में समावेशी आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिल सके। IHD रोजगार, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं से जुड़े मुद्दों, पर्यावरण और मानव विकास से जुड़े अन्य क्षेत्रों में काम करता है और इन विषयों पर होने वाली चर्चाओं में भी सक्रिय रूप से योगदान देता है। IHD का एक पूर्वी क्षेत्रीय केंद्र रांची में और एक कार्यक्रम कार्यालय पटना (बिहार) में स्थित है।

क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया

क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया (CCI) भारत की एक प्रमुख गैर-लाभकारी संस्था है, जिसकी स्थापना 1964 में कमलादेवी चट्टोपाध्याय ने भारतीय शिल्प विरासत की रक्षा और उसे आगे बढ़ाने के उद्देश्य से की थी। चेन्नई (तमिलनाडु) में स्थित यह संस्था देशभर में शिल्पकारों को सशक्त बनाने, उनके कौशल को विकसित करने और लुप्त होती कलाओं को फिर से जीवित करने के लिए राज्य परिषदों और अन्य साझेदारों के साथ मिलकर काम करती है। CCI हस्तशिल्प को केवल कला नहीं, बल्कि कारीगरों की आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हुए उसे संरक्षित करने पर ध्यान देती है। यह संस्था भारत सरकार और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम करती है, ताकि कारीगरों और उनकी कला के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़े।

भारतीय शिल्प का अर्थशास्त्र

हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र में रोजगार और मूल्यवर्धन का आकलन

INSTITUTE FOR HUMAN DEVELOPMENT
NEW DELHI • RANCHI
www.ihdindia.org

क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया